भारत सरकार

कृषि मंत्रालय

पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग

राज्‍य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- **1**10**5**

### दिनांक 23 मार्च, 2012 के लिए प्रश्न

विषय : अनन्‍य आर्थिक क्षेत्र (ई.ई.जेड.) में गहरे समुद्र में मात्स्यिकी

1105 : श्री सैयद अज़ीज़ पाशा:

 क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्‍या सरकार ने बारहवीं पंचवर्षीय योजनावधि हेतु गहरे समुद्र में मत्‍स्‍य उत्‍पादन और गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले जहाजों और नौकाओं के संचालन के लिए लक्ष्‍य निर्धारित किए हैं;

(ख) क्‍या यह सच है कि हाल में इन लक्ष्‍यों को संशोधित कर इन्‍हें कम कर दिया गया हैं;

(ग) यदि हां, तो ऐसे लक्ष्‍यों को संशोधित कर कम किए जाने के क्‍या कारण है;(घ) सरकार अनन्‍य आर्थिक क्षेत्र और अन्‍य क्षेत्रों में गहरे समुद्र में मात्स्यिकी की क्षमता का किस प्रकार विस्‍तार किए जाने का विचार रखती है; और

(ड.) गहरे-समुद्र में मात्स्यिकी के विस्‍तार हेतु अनुकूल वातावरण तैयार करने के लिए कौन-कौन से कदम उठाए जाने का विचार है?

**उत्तर**

# **कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री**

(डा0 चरण दास महंत)

(क): जी, नहीं।(ख) तथा (ग): प्रश्‍न नहीं उठता।

(घ) और (ड.): सरकार विशेषज्ञ समिति के गठन के माध्‍यम से गहरे समुद्र में मत्‍स्‍यन की सम्‍भावना का आकलन आवधिक आधार पर करती है। वर्ष 2009 में गठित भारतीय अनन्‍य आर्थिक क्षेत्र (ई.ई.जेड.) में संभावित मत्‍स्‍य संसाधनों के पुनर्वैधीकरण संबंधी विशेषज्ञ समिति के अनुसार, सम्‍भावित उत्‍पादन जिसका अनुमान वर्ष 2000 में पहले 3.92 मिलियन टन लगाया गया था, को अब पुनर्वैधतीकृत करके 4.41 मिलियन टन किया गया है। ईईजेड संबंधी बेड़ा योजना मात्स्यिकी संसाधनों के आकलन पर आधारित है। इसके अलावा, सरकार अन्‍तर मंत्रालयीय अधिकार प्राप्‍त समिति और विशिष्‍ट विशेषज्ञ वर्गों /समितियों के माध्‍यम से गहरे समुद्र में मात्स्यिकी के विकास के लिए अनुकूल वातावरण उपलब्‍ध कराने के लिए गहरे समुद्र दिशा-निर्देशों और नीतियों की समीक्षा करती है।

.......